

कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो, तभी हम सीख पाते हैं।
- अज्ञात

देश भर में उग्र विरोध

आइसलैंड एकमात्र देश है, जहां महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हमारे लिए संतोष की बात सिर्फ इतनी है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। इस मामले में भारत की रैंक 18 है।

राकेश जोशी

लगता है, कुछ मायनों में हमारा समाज आगे से पीछे की ओर जा रहा है। स्त्री-पुरुष समानता के मामले में हमारी रैंक तभी तो गिर रही है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि महिलाओं के साथ गैर-बराबरी बढ़ी है और उन्हें मिलने वाली सहायता घटी है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को दुनिया में 112वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल इस सूची में हमारी जगह 108वीं थी। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लिंगभेद कम तो हो रहा है लेकिन महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यालय और राजनीति में भेदभाव अभी भी मौजूद है।

आइसलैंड एकमात्र देश है, जहां महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हमारे लिए संतोष की बात सिर्फ

इतनी है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। इस मामले में भारत की रैंक 18 है। लेकिन स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (सर्वाइवल) के मामले में भारत पिछड़कर 150वीं रैंक पर आ गया है। इसी तरह भारत की गिनती उन देशों में हो रही है, जहां औरतों के लिए आर्थिक अवसर बेहद कम हैं। कंपनियों के बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.8 फीसदी है।

महिलाओं को हर स्तर पर भागीदारी दिलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई सारे कानून बने हैं लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें लागू कराने वाला अमला और समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी पितृसत्तात्मक सोच से उबर नहीं पाया है। समाज का ढांचा भी इसी सोच पर

आधारित है। यही वजह है कि महिलाओं को आज भी उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो न

सिर्फ निर्धन बल्कि मध्यवर्गीय परिवारों में भी खानपान पर पहला अधिकार पुरुषों का है। उनसे जो बचता है, वही महिलाओं के हिस्से आता है। इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। बीमारी और गर्भावस्था जैसी स्थितियों में भी स्त्रियों को पोष्टिक भोजन नहीं मिलता। उनकी बीमारियों के इलाज में कोताही की जाती है। यही हाल शिक्षा में है। परंपरागत सोच के तहत बेटे को बेटियों से बेहतर शिक्षा मिलती है।

नौकरी की बात करें तो हाल तक महिलाओं का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता था। अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में आ रही हैं तो वर्कप्लेस का माहौल उनके अनुकूल नहीं है। निजी कंपनियों गर्भावस्था में उन्हें छुट्टी और कुछ सहायता देने के बजाय उनसे पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर मानती हैं। राजनीतिक भागीदारी का आलम यह है कि महिला आरक्षण बिल वर्षों से लटका पड़ा है। तमाम कानूनी उपायों के बावजूद समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही। उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों में सजा की दर अब भी बेहद कम है। महिलाओं को हर स्तर पर बराबरी के अवसर देना न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरे समाज की जवाबदेही है, क्योंकि इसके बिना भारत की क्षमता आधी-अधूरी ही रहेगी।



भगवान के करीब

श्री श्री रवि शंकर।

एक परेशान मन भगवान के करीब नहीं जा सकता। भगवान के बारे में अपनी अवधारणाएं छोड़ दें। अपनी आँखें बंद करके बैठें और अपने अन्दर झाँकें। जब आप गहराई को अनुभव करेंगे, तब आपको स्वयं ही सत्य का बोध हो जायेगा। आप को उत्तर मिल जायेगा। सबसे अधिक शांत एवं आरामदायक जगह आप में है। अपने अन्दर की उस शांतिपूर्ण, शांत, शीतल, स्थिर, निर्मल गहरे में विश्राम करें जो मूल्यवान एवं कीमती है। सब शिकायतें दूर हो जाती हैं जब आप अपने मन की गहराइयों में गोते लगाते हैं। क्या आप ने विष्णु के नाग पर सोने की पौराणिक तस्वीर को देखा है? नाग जागरूकता एवं सतर्कता का प्रतीक है और इस पर प्रभु खुशी से सो रहे हैं। धन की देवी, लक्ष्मी भी वहीं विराजमान हैं। दिव्यता के प्रेम को विकसित करें। यह मदद करता है अगर आप उसके साथ हैं जो यह प्रेम खोज चुका है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

कमाई का रिकॉर्ड

मार्वल की सुपरहीरो फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' की ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी है। 'टाइटैनिक' की कमाई का रिकॉर्ड तोड़कर यह 'अवतार' के बाद विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बन गई है। टाइटैनिक की वर्ल्डवाइड कमाई 153 अरब रुपये थी, जिसे एंडगेम पीछे छोड़ चुकी है। केवल भारतीय बाजार में इस फिल्म ने रविवार तक 312.95 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। वैसे एवेंजर्स एंडगेम की जिस तरह रोजाना कमाई के नए कीर्तिमान रच रही है, उससे लगता है कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक से हॉलिवुड ने एक लंबी छलांग लगाई थी। निश्चय ही हॉलिवुड ने विश्व बाजार की नब्ज को पकड़ लिया है और उसकी फिल्में दुनिया भर के दर्शकों को चमकृत कर रही हैं। हॉलिवुड के साथ-साथ बॉलिवुड और अन्य भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों की कमाई भी बढ़ रही है। पहले किसी बॉलिवुड फिल्म का एक करोड़ कमा लेना ही खबर बन जाता था, पर अब तो पांच सौ करोड़ का क्लब भी बन गया है। 'दंगल' ने तो पूरी दुनिया में करीब 2000 करोड़ रुपये की कमाई की है जबकि बाहुबली-2 ने 650 करोड़, पीके ने 832 करोड़, बजरंगी भाईजान ने 626 करोड़ और सुल्तान ने 584.14 करोड़ की कमाई की है। लेकिन इसके बावजूद कारोबार के मामले में बॉलिवुड अभी हॉलिवुड ही नहीं चीनी सिनेमा से भी काफी पीछे है। जिस तरह से फिल्मों का आदान-प्रदान दुनिया भर में बढ़ा है, बॉलिवुड को कथ्य और तकनीक के स्तर पर कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। अपने बाजार में भी हॉलिवुड की चुनौती का सामना वह इसके बाद ही कर पाएगा।

हमारे शिक्षा ढांचे के पालनहारों को जवाब में कुछ कहना जरूरी नहीं लगता। भारत को नॉलेज पॉवर और मैनुफैक्चरिंग हब बनाना क्या इस पूर्णांक बांटने वाली शिक्षा पद्धति के बूते की बात है?

बड़े बदलाव की जरूरत

आरती सिंह

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की परीक्षाओं में साल दर साल नंबरों की मूसलाधार बारिश हमारी शिक्षा पद्धति को हंसी का पात्र बना रही है। इससे सीधा संकेत यह मिल रहा है शिक्षा में देर से सही, पर परीक्षा प्रणाली में तुरंत किसी बड़े बदलाव की जरूरत है। इस साल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 500 में 499 नंबर लाने वाले दो टॉपर्स और 2 लाख 40 हजार से ज्यादा 90 पर्सेंट से ज्यादा मार्क्स लाने वालों के बाद 10वीं के बोर्ड में 13 बच्चों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। इन सभी को 500 में से 499 अंक मिले हैं। 498 अंक लाकर 24 बच्चे दूसरे स्थान पर हैं। बारहवीं की एक टॉपर, आर्ट्स स्ट्रीम की हंसिका ने इंग्लिश में 99 मार्क्स को अपने साथ नाइसाफी बताते हुए अदालत जाने की बात कही है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और हिंदुस्तानी वोकल (संगीत) में उसने 100 में से 100 हासिल किए हैं। क्या ये विषय ऐसे हैं जिनमें हर सवाल के सौ टंच सही जवाब दिए जा सकें?

लगभग हर विषय में पूर्णांक पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या का लगातार बढ़ना यही बताता है कि हमारी परीक्षा पद्धति मीडियाक्रिटी के एक ढर्रे में



फंसकर रह गई है। तमाम स्कूल और कोचिंग संस्थान बच्चों को सिर्फ वह ढर्रा पकड़ाने के लिए, बच्चों को वह कुंजी थमाने के लिए बैठे हैं, जिससे अंकों का खजाना खुलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे बच्चों को रट्टू तोता बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अंक बच्चों और उनके मां-बाप को तात्कालिक खुशी देते हैं और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन का रास्ता खोलते हैं। उनके भीतर रचनात्मकता को बढ़ावा देना इनके अर्जेण्ड में ही

नहीं है। बच्चों में उत्सुकता, जिज्ञासा, खोजबीन की तड़प या किसी कोशल में असाधारण निपुणता पैदा करना तो अब शिक्षण जगत की कल्पना से भी परे हो गया है। कुल मिलाकर इससे देश में धंधेबाजों और पिछलग्गुओं की जमात पैदा हो रही है। शोध और अन्वेषण में भारत के फिसड्डी रह जाने की मुख्य वजह यही है।

वरिष्ठ भारतीय उद्यमी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों शिकायत करती हैं कि भारत में इंजीनियरों के पास सिर्फ डिग्री होती है, योग्यता नहीं। हमारे शिक्षा ढांचे के पालनहारों को जवाब में कुछ कहना जरूरी नहीं लगता। भारत को नॉलेज पॉवर और मैनुफैक्चरिंग हब बनाना क्या इस पूर्णांक बांटने वाली शिक्षा पद्धति के बूते की बात है? परीक्षा के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन और देशों में भी किया जाता है लेकिन उनका जोर विद्यार्थियों की प्रतिभा को उभारने पर होता है। चीन में माओ त्से तुंग ने काफी पहले कहा था कि अगर पांच प्रश्नों में से पांचों के जवाब कोई औसत ढंग से दे तो उसे 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक न मिलें, लेकिन कोई छात्र यदि एक ही प्रश्न का असाधारण और मौलिक उत्तर दे तो भी उसे 60 प्रतिशत अंक दे दिए जाने चाहिए। सवाल वही कि हमारे केंद्रीय शिक्षा बोर्ड क्या बच्चों के मूल्यांकन को लेकर लीक से हटने को तैयार होंगे?

सूटोके नववाले 5194				****			
				सूटोके नववाले 5193 का हल			
2	9	3	1	3	9	7	5
3	6	2	7	1	2	8	6
	7		6	2	4	5	2
7		1		6	4	5	2
1	3		4	9	3	4	6
			5	1	7	5	8
6	2	4		4	8	6	3
5	6	9	1	8	5	4	2
1		5	3	6	4	1	7
				8	5	4	9

अपना ब्लॉग पूंजी का इस्तेमाल

चीनी मिलें चीनी के सह-उत्पादों जैसे शीरा, खोई (बगास), प्रैसमड आदि से भी अच्छी कमाई करती हैं। इसके अलावा सह-उत्पादों से एथनॉल, बायो-फर्टीलाइजर, प्लाईवुड, बिजली व अन्य उत्पाद बनाकर भी बेचती हैं। पर इस साल पहले विलंब से आए मॉनसून के कारण सूखा पड़ने और बाद में अत्यधिक बेमौसम बारिश के कारण देश में गन्ने की फसल को काफी नुकसान हुआ। इससे महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन पिछले साल के 107 लाख टन से घटकर 55 लाख टन और कर्नाटक में 44 लाख टन से घटकर 33 लाख टन रहने की संभावना है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अनुसार चीनी मिलों को 14 दिनों के अंदर गन्ना भुगतान कर देना चाहिए। भुगतान में विलंब होने पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय होता है। लेकिन चीनी मिलें साल-साल भर गन्ने का भुगतान नहीं करतीं, उस पर ब्याज नहीं देतीं और किसानों की इस पूंजी का इस्तेमाल भी करती हैं। गन्ना किसानों की समस्या से निपटने के लिए चीनी उद्योग को लेकर एक अलग नीति बनाने पर भी विचार करना होगा।

